RAJYA SABHA

Wednesday, the 5th March, 1997/ 14the Phalguna, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock Mr. **Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Flood Control In Bihar

*161. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration to stop damage caused by floods in Bihar every year due to rivers flowing from Nepal;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ganga Flood Control Commission has prepared comprehensive flood management plans for all sub-basins of Ganga, in respect of all concerned States including those tributaries flowing from Nepal to Bihar, and sent to the State Governments for their detailed investigation and implementation. The State Government of Bihar has been undertaking various flood management measures which have provided reasonable degree of protection to an area of 18.89 lakh. ha. out of a flood prone area of 42.60 lakh ha. so far. The schemes are undertaken by the State out of the State plan funds depending on the *interse* priority decided by them.

The Central Government is also providing financial assistance to Bihar for implementing flood proofing programme in the State during 8th Plan which is proposed for continuation during 9th Plan. 98 flood proofing schemes have been cleared and an amount of Rs. 1.5 crore was released during 1995-96 to the State as advance for initiating the work. However so far the State Government has spent only Rs. 27 lakh. During 1996-97 this Ministry had provided for Rs. 7 crore but in view of poor expenditure, while finalising revised estimates, it has been reduced to Rs. 1 crore, the release of which would depend upon utilisation certificate for the year 1995-96.

The Central Government is also holding discussions with the His Majesty's Government of Nepal regarding construction of storage reservoirs and embankments on common rivers which would benefit both the countries. Extending embankments on Lalbakeya, Kamla, Bagmati and Khando rivers into Nepal territory are under active consideration and the work on Lalbakeya embankment is expected to start very early. Investigations for Sapta Kosi High Dam in Nepal are also expected to be taken up jointly with Nepal shortly. A joint project for setting up meteorological and hydro meteorological stations on common rivers with laval which would provide data for effcient flood forecasting on these rivers in under implementation.

श्री गया सिंह: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया वही है जो पहले से जवाब आ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह समस्या क्योंकि अभी हाल में आपने बंगला देश

और भारत का जो एक एतिहासिक समझौता किया था उससे बंगला देश को तो लाभ होगा, राजनीतिक तौर पर हिन्दुस्तान को भी लाभ होगा। लेकिन पिछले वन डिकेड से नेपाल में बारिश होती है और बिहार के 10-12 जिलों में बाढ़ हो जाती है। बिहार में बारिश नहीं भी हुआ तो भी बिहार में नेपाल के पानी के चलते बाढ़ आ जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, यह जानना चाहता हूं कि एट्थ फाईव ईयर प्लान की इन्होंने चर्चा की और यह कहते हैं नाईथ फाईव ईयर प्लान में यह कंटीन्यू करेगा लेकिन मुख्य रुप से हमारा सवाल है कि यह जो पिछले आजादी के बाद से हर साल लाखों आदमी घर-द्वार छोड़कर बाढ़ के चलते 6 महीना बाहर रहते हैं, तो क्या इसी महत्वपूर्ण इस विषय पर संयुक्त मोर्चा की सरकार और आपका मंत्रालय निकट भविष्य में नेपाल से कोई समझौता करने का इरादा रखता है या उस संबंध में कोई अभी तक आफिशियल मीटिंग हुई है या क्या प्रोग्रेस है, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, पिछले 60 दशक से नेपाल से बहने वाली नदियों के बाढ़ और उनकी समस्याओं के बारे में नेपाल से बातचीत की कोशिश हो रही है। महाकाली संधि के बाद दरवाजा अब खुला है, क्योंकि उससे पहले नेपाल का रूख अनुकूल नहीं होता था। उसके बाद नेपाल के जल संसाधन मंत्री और भारत के जल संसाधन मंत्री की आपस में बातचीत हुई है और उसकी अधिकारियों के तौर पर इसकी बातचीत चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल की नदियों से बिहार में जो बाढ़ आती है उनके लिए हम जल्द कोई रास्ता और परियोजना निकालेंगे।

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने तो कोई स्पष्ट नहीं कहा, जैसा जनरल जवाब पिछली बार दिया था वही दिया है। मैं फिर आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्ट रूप से एक ही सवाल कर रहा हूं। क्या आपके हिसाब से 1997 तक मंत्री लेविल तक नेपाल से कोई बातचीत हो सकेगी जब आप इतना महत्वपूर्ण समझते हैं, और दूसरा, इसी के साथ कि कोशी में जो बांध 1955 में बनाया गया था वह नेपाल के पानी और उसके साथ मिट्टी के चलते बांध नदी के बराबर होता जा रहा है। क्या उसके संबंध में भी कुछ करेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, 1955 के बने हुए बांध की अब मियाद पुरी हो चुकी है और यह सही है कि नेपाल से बहने वाली नदियां अपने साथ रेत और गाद बहुत लाती हैं। उसके हल करने के लिए हमें नेपाल से ही सम्पर्क करना पड़ेगा। नेपाल हर बात में सतर्क रहता है और इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाती है और यह बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज मुझे अच्छा यह लग रहा है कि माननीय सदस्य की मैं प्रशंसा करुंगा कि आम तौर पर बाढ़ के सवाल को जब बाढ़ आती है तभी पार्लियामेंट से लेकर देश की जनता तक बहस करती है।

लेकिन आज बिना मौसम के यह बहस हो रही है और मैं चाहूंगा कि जब कोई समस्या आती है तो उसके आतंक के कारण हम लोग उस समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं और उसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। आज जब इस समस्या पर सोचा जा रहा है बाढ़ के अलावा वाले समय पर तो सारा प्रयास यही हो रहा है कि नेपाल सरकार से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए और कोई योजना तैयार की जाए।

श्री जलालुदीन अंसारी: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता है, उससे बहुत सारी बालू और दूसरी चीजें आती है और हमारे बिहार का वह हिस्सा प्रतिवर्ष तबाह और बरबाद हो जाता है। सरकार बराबर कहती रही, पूर्ववर्ती सरकार भी कहती रही है और हमारे माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम नेपाल से इस संबंध में बातचीत करेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा कि यह तो वर्षों से आश्वासन मिल रहा है कि नेपाल सरकार से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाएगा लेकिन दुख की बात है कि अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बिहार की इस भयानक बरबादी को रोकने के लिए और राहत देने के लिए नेपाल सरकार से बातचीत करके आप एक समझौता करें ताकि इस विभीषिका से बिहार की जनता को राहत मिल सके। मैं आश्वासन चाहूंगा कि इस दिशा में वे कौन सा प्रयास करने जा रहे हैं, यह सदन को बताने का कष्ट करें।

†मंत्री जलालुद्दीन अंसारी: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता है, उससे बहुत सारी बालू और दूसरी चीजें आती हैं और हमारे बिहार का वह हिस्सा प्रतिवर्ष तबाह और बरबाद हो जाता है। सरकार बराबर कहती रही, पूर्ववर्ती सरकार भी कहती रही है और हमारे माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम नेपाल से इस संबंध में बातचीत करेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा कि यह तो वर्षों से आश्वासन मिल रहा है कि नेपाल सरकार से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाएगा लेकिन दुख की बात है कि अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बिहार की इस भयानक बरबादी को रोकने के लिए और राहत देने के लिए नेपाल सरकार से बातचीत करके आप एक समझौता करें ताकि इस विभीषिका से बिहार की जनता को राहत मिल सके। मैं आश्वासन चाहूंगा कि इस दिशा में वे कौन सा प्रयास करने जा रहे हैं, यह सदन को बताने का कष्ट करें।

†Transliteration in Arabic Script

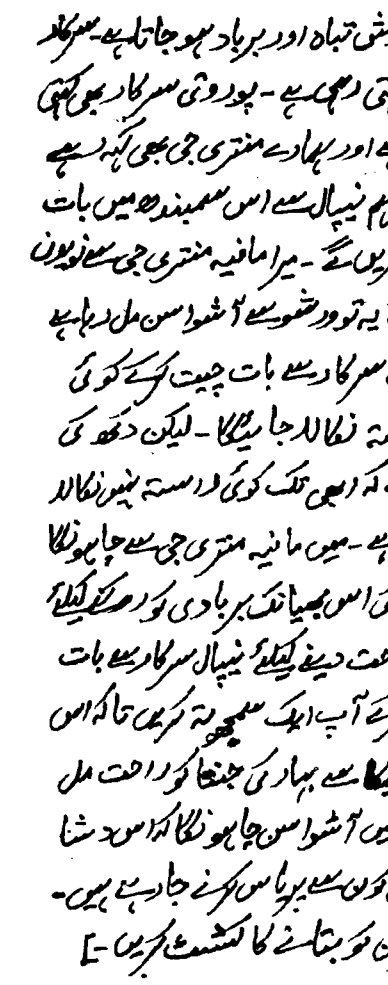

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, अभी बातचीत अधूरी ही है और कोशिश इस बात की की जा रही है कि कोसी बांध माननीय गया सिंह जी ने उल्लेख किया, उसे और ऊंचा किया जाए और इसके लिए बात हो रही है। नेपाल सरकार अगर सहमत हो जाती है और मेरा ऐसा विश्वास है कि वह शीघ्र ही सहमत हो जाएगी तो बाढ़ को रोकने के लिए उसको ऊंचा करने की योजना बनाई जाएगी।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: माननीय सभापति जी, नेपाल से हो या हिमालय से जो नदियां आती हैं, वे हों, उन नदियों से हर साल बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है और उसके कारण बिहार, बंगाल और असम में बहुत ही नुकसान होता है। हर साल जमीन, खेती उत्पादन और नदी के किनारे बसे गांव हों या शहर हों, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इन सबको रोकने के लिए और पानी से सिंचाई के लिए बहुत ही फायदेमंद गंगा-कावेरी योजना जो डॉ० के०एल० राव ने जो कि प्रख्यात इंजीनियर थे, उन्होंने प्रस्तावित की थी। अभी सरकार की जो ग्लोबलाइज़ेशन और लिब्रलाइज़ेशन की पॉलिसी है, उसके आधार पर सरकार क्या इस प्रस्ताव पर विचार करेगी?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, गंगा-कावेरी योजना तो दूसरा विषय होगा, इसके लिए अलग नोटिस की जरुरत है। जहां तक नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बिहार को होने वाले नुकसान का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि इस विषय पर वार्ता बहुत आगे बढ़ चुकी है और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि बिहार में करीब 98 फ्लड-प्रूफिंग स्कीम्स सैक्शन की गई हैं जिसके लिए डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया था लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 27 लाख रुपए का उपयोग किया। 1996-97 में मंत्रालय 7 करोड़ रुपए देना चाहता था लेकिन पिछली पूअर परफॉरमेंस को मददे-नज़र रखते हुए उसे घटा कर 1 करोड़ कर दिया गया। आपने इस पर विचार-विमर्श करने के लिए या इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए कभी कोई उच्च-स्तरीय दल भेजा है और उसने क्या रिपोर्ट पेश की है, कृपा करके यह बता दें।

दूसरे, क्या मंत्री महोदय को पता है कि लालबाकेया, कमला, बागमती और खाण्डो नदियों पर हम महाकाली संधि के बाद यह उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ उसके एम्बैंकमेंट्स को बढ़ाने के लिए या उसके पानी को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था की जाएगी? पर नेपाल की चीन से भी कुछ संधियां हुई हैं और चीन ने उनको कुछ प्रपोजल दिये हैं कि वह इन नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करेगा और बिजली उत्पादन से नेपाल के चारों तरफ जो सड़क बन रही है उसमें लाइट की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और दूसरी सारी व्यवस्थाओं का संचालन होगा। बिजली उत्पादन केन्द्र बनने से वहां पानी की छूट में और उसके रुकाव में टाइम-टाइम पर खतरा पैदा हो सकता है। नेपाल के तराई इलाकों में जहां बिहार बसा हुआ है, उसके बारे में आपने कोई जांच पड़ताल की है और अगर की है तो नेपाल से इस संबंध में क्या बात की है?

श्री जनेश्वर मिश्र: फ्लड प्रूफिंग के कार्यक्रम में जो बिहार सरकार की तरफ से शिथिलता आई है कि उसने

डेढ़ करोड़ में से केवल 27 लाख रुपये खर्च किये। जब तक उपयोग करने का, यूटीलिटी सर्टीफिकेट जिसको कहते हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक धन निर्मुक्त करना मुश्किल है और इसीलिए सात करोड़ को काटकर एक करोड़ किया गया है क्योंकि आम तौर पर इस तरह के कार्यक्रम में राज्य सरकारों की दिलचस्पी कम रहती है। फिर भी मुजफ्फरपुर और पोनिया जिले में फ्लड प्रूफिंग का कार्यक्रम चल रहा है और फ्लड प्रूफिंग के काम को आगे बढ़ाने और मानिटरिंग के लिए अभी एक मीटिंग वहां के ऐक्सपर्ट्स की बुलाई गयी है और हम समझते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। रह गयी बात नेपाल से बहने वाली तीन-चार नदियों की, उनके बारे में नेपाल सरकार से हम लोगों ने तटबंध को और ऊंचा बढ़ाने की बात की थी, खास तौर से वहां के जल संसाधन मंत्री से। इन्होंने भी इस सम्बन्ध में सहमति जताई है। कुछ नदियां जो तिब्बत से बहकर आती है, उसके बारे में चीन से उनकी बातचीत हुई होगी और वह हमारे मंत्रालय और सरकार का विषय नहीं है, यह विदेश विभाग ही बता सकता है कि क्या बातचीत हुई है।

Bridges on National Highways in Uttar Pradesh

*162. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of bridges constructed on National Highways in Uttar Pradesh during the last three years;

(b) the number of bridges proposed to be constructed during the current year together with the details thereof; and

(c) the target proposed to be fixed for construction of bridges during the Ninth Five Year Plan?

MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) Five number of bridges were constructed on National Highways in Uttar Pradesh during the last three years.

(b) Five bridges are targetted to be completed during the current yer (1996-97). The details thereof are as under:—

(1) Bridge over Sarain river on Sitapur bypass on NH-24.

(2) Khajuri bridge in Km. 70 of NH-29.

(3) Maghai bridge in Km. 88 of NH-29.

(4) Ami bridge in Km. 188/2 of NH-29.

(5) Taraina bridge in km. 165 of NH-29.

(c) The 9th Five Year Plan is yet to be finalised.

श्रीमती मालती शर्मा: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के भाग "ग" के उत्तर में मैं यह पूछना चाहती हूं कि नवी पंचवर्षीय योजना में क्या दिल्ली से हरिद्वार तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कोई योजना है? दूसरा, स्टेट हाईवेज़ में भी क्या यह योजना है कि पानीपत से खटीमा मार्ग जो तितावी शुगर मिल के पास से होकर गुजरता है, वहां हिंडन नदी का एक पुल है जिस पुल के ऊपर विभाग ने एक बोर्ड लगा दिया है कि इससे अधिक भार इस पुल के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए? लेकिन एक तो वह पुल सिंगल है और उसके नीचे के तमाम वैल्डर कट चुके हैं। एक बार वहां दुर्घटना हो चुकी है और भविष्य में भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है जब कि तितावी शुगर मिल का सारा गन्ना वहां से गुजरता है और हरियाणा को जाने वाला पूरा ट्रैफिक भी वहां से गुजरता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि केन्द्र की सरकार जो दो वर्ष से उत्तर प्रदेश में है, क्या इस मार्ग और इस पुल की तरफ तुरन्त ध्यान देकर आप यह बताएंगे कि नवीं पंचवर्षीय योजना में इसके निर्माण की कोई योजना आपके पास है?

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, generally, so far as declaration of the highways is concerned, we have not declared any highways because of financial crunch. After the budgetary allocation I find that there is some relief. I will think over, consider the project which the hon. Member has mentioned.

With regard to the Delhi-Hardwar State highway, it is with the State. Therefore, the State Government has to take care of it. I will also take into consideration the bridge at Panipat, which the hon. Member has mentioned.

श्रीमती मालती शर्मा: एक प्रश्न जो इसी का महत्वपूर्ण भाग एक था कि दिल्ली से हरिद्वार तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बात है इसका उत्तर मैं मंत्री जी से चाहती हूं। कुम्भ मेला आने वाला है और इस रास्ते